



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 229 ]  
No. 229]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 5, 1997/अग्रहायण 14, 1919  
NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 5, 1997/AGRAHAYANA 14, 1919

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना सं. 57 (पी एन)/97-02

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 1997

**विषय :—** निर्यात एवं आयात नीति अप्रैल, 1997-मार्च, 2002-नेप्था के आयात से सम्बन्धित नीति।

**फा. सं. आई पी सी/4/5/( 296 )/92-97/552.**—वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं. 25, 97-02 दिनांक 5 दिसम्बर, 1997 की ओर ध्यान दिलाया जाता है जिसके अनुसार इस सम्बन्ध में जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार विद्युत क्षेत्र में ईंधन के रूप में वास्तविक उपभोगता द्वारा नेप्था का आयात भी अनुमत है।

2. उपर्युक्त के अनुसरण में, विदेश व्यापार महानिदेशालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली द्वारा जारी आयात लाइसेंसों के प्रति निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वतन्त्र विद्युत उत्पादकों (आई पी पीज) को नेप्था/ईंधन तेल के आयात की अनुमति होगी।

- (1) स्वतन्त्र विद्युत उत्पादकों को नेप्था के आयात के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा प्रदान किए गए लाइसेंस की आवश्यकता होगी जिसके लिए प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1), 1997-2002 के परिशिष्ट 8 में निर्धारित प्रपत्र में आवेदन किया जाएगा।
- (2) स्वतन्त्र विद्युत उत्पादकों द्वारा नेप्था/ईंधन तेल का आयात वास्तविक उपभोगता शर्त के अधीन होगा और यह पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं मात्रा तथा ईंधन लिंकेज पत्र में उल्लिखित ईंधन के प्रकार के आधार पर विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा प्रदान किया जाएगा। लाइसेंस की अवधि निर्यात एवं आयात नीति के प्रावधानों के अनुसार होगी। निर्यात एवं आयात नीति में दी गई लाइसेंस की सामान्य अवधि में वृद्धि करने का निर्णय प्रशासनिक मंत्रालय की सलाह से विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा लिया जाएगा।
- (3) आई पी पी विद्युत मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और जिस तेल कम्पनी द्वारा उन्हें लिंकेज प्रदान किए गए हैं, को अपने आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। तेल कम्पनी अपनी टिप्पणियां पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के पास 10 दिन के भीतर भेज सकती हैं और यदि आवेदन प्राप्ति के 10 दिन के भीतर कोई टिप्पणी नहीं प्राप्त होती तो यह मान लिया जाएगा कि तेल कम्पनी की प्रस्तावित निर्यातों के बारे में कोई आपत्ति नहीं है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तेल कम्पनी से टिप्पणी प्राप्त होने पर एक सप्ताह के भीतर विद्युत मंत्रालय और विदेश व्यापार महानिदेशालय को अपनी टिप्पणी भी भेजेगा। विद्युत मंत्रालय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के विचार/टिप्पणी पर विचार करने के पश्चात् विदेश व्यापार महानिदेशालय को आई० पी० पी० आवेदन पर अपनी विशिष्ट सिफारिशें भेजेगा। विदेश व्यापार महानिदेशालय आई पी पी संबंधी आयात लाइसेंस के आवेदन पर उचित निर्णय लेगा।
- (4) वास्तविक आयात के समय, सीमा शुल्क प्राधिकारी आयात के बंदरगाह पर विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा मंजूर किए गए आवश्यक

लाइसेंस की उपलब्धता की जांच और संतुष्टि करेंगे तथा वास्तविक प्रयोगकर्ता की शर्तों के अनुपालन की निगरानी करने के लिए, वे अनंतिम आधार पर प्रारम्भ में मूल्यांकन की अनुमति दे सकते हैं बशर्ते अंतिम प्रयोग का सबूत प्रस्तुत करने के तहत इसे अंतिम रूप दिया जाए। इस उद्देश्य के लिए, राज्य विद्युत बोर्ड अंतिम प्रयोग संबंधी प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकरण के रूप में नामित किया जा सकता है चूंकि विद्युत खरीद करार राज्य विद्युत बोर्ड और आई पी पी के बीच होगा।

- (5) आयात केवल पेट्रोलियम नियमावली, 1976 के नियम 16 के तहत "तेल पतन" के रूप में घोषित पतनों के जरिये ही किया जा सकता है।
  - (6) ऑफ स्पैक/उपयोग में न लाई गई आयात की मात्रा के निपटान की अनुमति केवल वाणिज्यिक आधार पर परस्पर सहमत शर्तों पर सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रमों के जरिये ही दी जा सकती है।
  - (7) आई पी पी द्वारा आयात के लिए लाइसेंस की मंजूरी देते समय विदेश व्यापार महानिदेशालय, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आई पी पी द्वारा वास्तविक प्रयोगकर्ता की शर्तों का सख्ती से पालन किया जा रहा है, अन्य आवश्यक शर्तें लगा सकता है।
  - (8) आई पी पी प्रत्यक्ष रूप से या आई पी पी के संकाय (निगमित या अनिगमित) के जरिये या सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रमों के जरिये या संयुक्त उद्यम क्षेत्र की कम्पनियों, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र का तेल उपक्रम साझीदार हो, के जरिये आयात कर सकता है।
  - (9) आई पी पी ईंधन प्रबन्ध योजना या सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रमों के जरिये सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रमों के साथ समझौता कर सकता है।
  - (10) आई पी पी आयात टर्मिनल/भंडारण सुविधाओं को अपने आप, तेल क्षेत्र की सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों अथवा उन संयुक्त उद्यमों के माध्यम से जिनमें तेल क्षेत्र की सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई पार्टनर हैं अथवा किसी निजी पार्टी जिनमें विदेश कम्पनी अथवा नेप्था/ईंधन तेल के आयात हेतु उसकी संयुक्त उद्यम की पार्टी शामिल हैं, द्वारा उपयोग करने का विकल्प चुन सकती है।
4. इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

एस. बी. महापात्र, महानिदेशक, विदेश व्यापार

### MINISTRY OF COMMERCE

Public Notice No. 57 (PN)/97-02

New Delhi, the 5th December, 1997

**Subject : Export and Import Policy April, 1997—March, 2002—Policy relating to import of Naphtha.**

**F.No. IPC/4/5(296)/92-97/552.**—Attention is invited to Ministry of Commerce Notification No. 25/97-02 dated 5th December, 1997 according to which import of Naphtha is also permitted by Actual Users as fuel in Power Sector in accordance with a Public Notice issued in this behalf.

2. In pursuance to the above, import of naphtha/fuel oil shall be permitted by the Independent Power Producers (IPPs) against the import licences issued by the Directorate General of Foreign Trade, Udyog Bhawan, New Delhi subject to the following conditions :—
  - (i) Import of naphtha by IPPs would require a licence to be granted by Directorate General of Foreign Trade (Headquarters), for which application shall be made in the form prescribed in Appendix 8 of the Handbook of Procedures (Volume 1), 1997-2002.
  - (ii) The import of naphtha/fuel oil by IPPs shall be subject to Actual User condition and shall be granted by DFT on the basis of quantity and type of fuel as mentioned in the fuel linkage letter and No Objection Certificate issued by Ministry of Petroleum & Natural Gas. The period of licence shall be as per provisions of Exim Policy. The decision to extend the period of licence beyond the normal period as provided in the Exim Policy shall be taken by the D.G.F.T. in consultation with Administrative Ministry.
  - (iii) IPPs may submit copies of their applications simultaneously to the Ministry of Power, Ministry of Petroleum & Natural Gas and the oil company through which linkages have been given to them. The oil company shall send its comments within 10 days to the Ministry of Petroleum & Natural Gas and if no comments are received within 10 days on receipt of application from IPP, it will be assumed that oil company has no objection to the proposed imports. Ministry of Petroleum & Natural Gas shall also send its comments within a week on receipt of comments from the oil company to the Ministry of Power and DGFT. Ministry of Power after considering the views/comments of Ministry of Petroleum & Natural Gas shall make their specific recommendations on the IPP application to the DGFT. DGFT will take appropriate decision on the application for import licence to IPP.
  - (iv) At the time of actual import, the Customs Authorities at the port of import shall verify and satisfy themselves about the availability of the necessary licence sanctioned by the DGFT and for the purpose of monitoring the compliance of actual user conditions, they may allow the assessment initially on provisional basis subject to finalisation on the basis of submission of proof of end-use. For this purpose, the State Electricity Board (SEB)

may be designated as the authority to issue the end-use certificate as the Power Purchase Agreement (PPA) would exist between SEBs and IPPs.

- (v) The import can be done only through the ports declared as 'Oil Port' Under Rule—16 of the Petroleum Rules 1976.
- (vi) Disposal of off-spec/unutilised quantity of imports will be allowed to be done only through oil PSUs on terms mutually agreed on commercial basis.
- (vii) While granting the licence for import by IPPs, DGFT may stipulate such other conditions which may be necessary to ensure that actual user conditions being strictly observed by the IPPs.
- (viii) The IPPs may source an import either directly or through consortium of IPPs (incorporated or un-incorporated) or through oil PSUs or through joint venture companies in which an Oil Public Sector Undertaking is a partner.
- (ix) The IPPs may tie up for the import with the oil PSUs either under Fuel Management Scheme or through facilitation by the Oil PSUs.
- (x) The IPPs may opt to utilise the import terminal/storage facilities of their own, oil PSUs or those of JVs in which an Oil PSU is a partner or of any private party, including foreign company or its JV for import of naphtha/fuel oil.

4. This issues in public interest.

S. B. MOHAPATRA,  
Director General of Foreign Trade

